के सहारे अपनी सरकार चलाती रहें । प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को ऐसा पानी दिया है कि वह 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है । ऐसे पत्थर दिये हैं जो करोड़ों टन सीमेंट पैदा करने की क्षमता रखता है । ऐसा प्राकृतिक सौन्दर्य दिया है कि जिस को देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेश से भी हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। इन स्रोतों के दोहन करते बर्खास्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये थे और यह संकल्प लिया था कि हिमाचल प्रदेश को आत्म-निर्भर बनायेंगे और स्वावलंबी बनायेंगे और उन्होंने एक तीन सूत्री कार्यक्रम बनाया था । नम्बर-1, प्रदेश में नये आर्थिक साधन जुटायेंगे नं. 2 केन्द्र से अपने अधिकार लेंगे और नं. 3 फजूलखर्ची पर रोक लगायेंगे आज मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उस मत की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत उन्होंने यह कहा था कि हम दिल्ली से अपने अधिकार लेंगे । आज जो प्रदेश गैस पैदा करता है उसका रायल्टी का अधिकार मिला हुआ है, जो प्रदेश तेल पैदा करता है वह रायल्टी का अधिकार रखता है, जो कोयला पैदा करता है वह भी रायल्टी का अधिकार रखता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो बिजली पैदा करता है उसको उस अधिकार से वंचित रखा गया है । यह लगभग दो सौ करोड़ रुपये प्रति वर्ष बनते हैं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार को असंवैधानिक तरीके से हिमाचल प्रदेश में तोड़ा गया । वह इस चीज के लिए प्रयास कर रही थी कि यह अधिकार उसको मिले और सरकार ने सैद्धांतिक तौर से इसको स्वीकार भी किया था कि 1990 के बाद जो हिमाचल प्रदेश की धरती पर इस प्रकार की परियोजनायें बनेंगी उनके लिए उसको 12 परसेंट निःशुल्क बिजली मिलेगी । लेकिन हमारी सरकार इस बात के लिए भी प्रयास कर रही थी कि 1990 से पहले भी हिमाचल प्रदेश की धरती पर जो परियोजनायें बनी हैं उसमें भी उसको रायल्टी मिलनी चाहिए । यह मांग उन्होंने चला रखी थी, लेकिन उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया । आज इस मांग ने जन-आन्दोलन का रूप ले लिया है । आज हिमाचल प्रदेश की ठंडी धरती से, देव भूमि से, लोगों ने निर्णय लिया है कि वहां के पंच प्रधान और जनता के प्रतिनिधि लगभग पांच हजार की संख्या में 10 मई को दिल्ली की इस तपती धरती पर धरना देंगे और अपनी मांगों के समर्थन में धरना देंगे और अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे । जैसा कि मैंने आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान भारतीय जनता पार्टी की इस मांग की तरफ दिलाया है वहां मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से अपने संचार मंत्री से आग्रह करूंगा कि उन्हें वे आज केन्द्र में बैठ कर सरकार के संचार मंत्री हैं वहां वे हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि भी हैं, वे हिमाचल प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वे इस मांग को, हिमाचल प्रदेश की जनता की मांग को, भारतीय जनता पार्टी की मांग को, पूर्ण रूप से अपना समर्थन और सहयोग देंगे और इन मांगों को, मनवाने में सफलता प्राप्त करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति धन्यवाद करता हूं ।

THE BEEDI AND CIGAR WORKERS (CONDITIONS OF EMPLOYMENT) AMENDMENT BILL, 1990

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Now we will take up the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Amendment Bill, 1990.

Mr. Sangma.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move :

"That the Bill to amend the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966, be taken into consideration."

The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 has been enacted to provide for the welfare of the workers in beedi and cigar establishments and to regulate the conditions of their work and matters connected therewith.

Beedi and Cigar Industry, essentially an agro-based industry is mainly concentrated in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal. It provides employment to about 44.72 lakh workers most of whom belong to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. The industry is, by and large, unorganised as only a small percentage of production is undertaken in regular establishments.

The Act is enforced by the State Governments. They were experiencing certain difficulties in effective implementation of the Act. In order to overcome such difficulties and to enlarge the scope of coverage of beedi workers, a Bill was introduced in the Rajya Sabha on 30th December, 1987 and was passed by the House on 14th March, 1989. While it was pending in Lok Sabha, the 8th Lok Sabha was dissolved and the Bill lapsed. The same Bill had been re-introduced in Rajya Sabha on 30th May, 1990. The Bill seeks to make amendments which would not only make provisions regarding conditions of work more favourable for the workers but also facilitate enforcement of the existing provisions.

Some of the proposed amendments are :—

(i) To extend the coverage of the Act to employees working in godowns and warehouses and also those who are working with the permission of or under agreement with both the employer and contractor;

(ii) To make the provision regarding calculation of overtime wages to the workers employed on piece-rate basis more clear and unambiguous;

(iii) To confer on the appellate authority the powers of civil court for the purpose of compelling attendance of witnesses and compulsory production of records;

(iv) To reduce the number of female employees from 50 to 30 for providing a suitable creche facilities inside the industrial premises by the employer for the children under the age of six years of such female employees;

(v) To make penal provisions more stringent;

(vi) To empower the State Govts. to prescribe the time limit within which a dispute between an employer and employee relating to the issue of raw materials by the employers to the employees, payment of wages for the beedi and cigar, or both, rejected by the employer etc. shall be referred for settlement.

India has ratified the Labour Inspection Convention No. 81 of the International Labour Organisation. Accordingly, the Bill also seeks to introduce a provision that Labour Inspectors shall treat as absolutely confidential the source of any complaint regarding the breach of any provisions of the Act.

These amendments to the Act would go a long way to remove the administrative and practical difficulties faced by the implementing agencies in enforcing the provisions of the Act.

With these words, I commend the Bill for unanimous support of this august House.

The question was proposed.

3.00 P.M.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह बात तो समझ में आ सकती है कि 1988-89 का जो बिल लैप्स हुआ, उसको आप इस समय इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा होता अगर एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी का निवारण करने के साथ-साथ इस उद्योग में जो लगे हुए लाखों, आपने स्वयं माना है कि गरीब तबके के लोग हैं, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी इसमें बहुत से प्रोविजन ले आ सकते थे। अब जब यह इन्ट्रोड्यूज हो रहा है, राज्य सभा में, तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसे प्रेस्टिज का इश्यू नहीं बनाना चाहिए। उसे अपनी तरफ से भी ओरिजनल ऐक्ट में कुछ प्रोविजन जोडकर, जो आज उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने वाले साबित हो सकते हैं, उनको अमेंडमेंट के तौर पर सरकार खुद ले आए और एक कम्प्रहैंसिव बिल अगर इस रूप में पास किया जा सके तो वह ज्यादा अच्छा होगा।

महोदय, इस क्षेत्र में लाखों लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनकी वर्किंग कंडीशन्स ठीक नहीं हैं। आपने गवेजन इन्क्लड किये हैं। लेकिन इन-ह्यूमन कंडीशन में उनको काम करना पड़ता है। उनकी हैल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं हैं। उनके बच्चों के लिए, जब ये जिंदगीभर एक ठेकेदार के नीचे या इम्प्लायर के नीचे काम करते हैं, फिर भी इस बारे में उनको किसी प्रकार की गारण्टी नहीं है। उनकी जीविका की दृष्टि से वेलफेयर वरकर्स फंड आपने बनाया जरूर है परन्तु जो मैन्फैक्चर्ड बीडियों पर से सेस वसूल होता है, वह अकाउंट बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। आज वेलफेयर स्कीम को बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कारण से इस सेस को भी रिवाइज करने की बात सोची जानी चाहिए ताकि मजदूरों की हालत सुधारने के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यवस्था की जा सके। कल भी आपने जब चाइल्ड लेबर की बात की थी तो यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा काम करते हैं। फेमली सर्कमस्टांसेज की मजबूरियों में इस काम को करते-करते अगर उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था साथ हो जाए तो उसका इंतजाम ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसका भी आप विचार करें कि सारे देशभर के लिए क्या एक कम्प्रहैंसिव ला इन सारी बातों को संभालने के लिए किया जा सकता है।

फिनिशिंग वेजेज भी अलग-अलग हैं, चोरी करती हैं, यूनीफार्म नहीं है। इस संबंध में भी सरकार कुछ प्रावधान करे और ऐसा कानून बनाए कि इसका पालन न करने वालों के ऊपर पिनल एक्शन लिया जा सके। हम सदिच्छा प्रकट तो करें लेकिन सदिच्छा को कार्यान्वित करने के लिए अगर व्यवस्था नहीं होती है तो फिर हमारी सदिच्छाएं ठीक प्रकार से कारगर साबित नहीं होती हैं या फिर हमें स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करनी चाहिए कि कानून में पाबंदी होने के बाद भी जो लोग सरकारी अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर के इन सारे नियमों को लागू करवाने के रास्ते से बच निकलते हैं और संरक्षित लाभ इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को नहीं मिल पाता है तो कुछ व्यवस्था उसके लिए होनी चाहिए। आप एक ऐसी मोनिटरिंग एजेंसी नियुक्त करें जो समय-समय पर ऐसे केन्द्रों पर खुद जा कर निरीक्षण करे कि कौन से नियम लागू किए जा रहे हैं और कौन से लागू करना आवश्यक है।

इस क्षेत्र में महिलाएं भी काम करती हैं। वे अपने घरों पर भी बीड़ियां बनाने के लिए

ले जाती हैं। लेकिन ऐसे केन्द्रों पर भी महिलाएं बीड़ी बनाने का काम करती हैं। उनके साथ शोषण किये जाने की संभावनाएं हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि इसको कैसे रोकें। पुरुषों और महिलाओं के वेजज में भी अन्तर है। बीड़ी बनाने का तो ऐसा काम है चाहे पुरुष बनाएं या महिलाएं, इनके लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तक यह अंतर क्यों चला आ रहा है, इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम इम्प्लायमेंट की शर्तों में इन बातों की व्यवस्था कर सकते हैं कि इस तरह का अंतर इसमें न हो और महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त करवाया जा सके।

इस क्षेत्र में कोआप्रेटिव्ज को बढ़ाने के लिए भी सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। महिलाएं खुद अपनी छोटी-छोटी सहकारिता समितियां बनाकर खुद अपने परिश्रम और लागत पर फायदा कोआप्रेटिव्ज के माध्यम से उठा सकें लेकिन इस बात की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जा सकता है, सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए।

मैं समझता हूं इन मजदूरों या काम करने वाले लोगों की वर्किंग कंडीशंस, वेजेज और प्रोविडेंड फंड की बातों पर कानून में कुछ अधिक कड़ाई की भाषा लिखवाने के लिए सारी मशीनरी की व्यवस्था इस कानून में जोड़कर सरकारी अमेंडमेंट के माध्यम से होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 6 साल के बाद रेगुलर रोस्टर के तरीके से यह कानून आ सका है। अब यह जो अपर्चुनिटी मिली है, मेरा मंत्री महोदय को सुझाव होगा कि इसी कानून में सरकार की तरफ से दो-तीन और संशोधन जोड़कर इसी समय एज अमेंडेड कानून को पास करवा लें। ताकि इस सोशल लेजिस्लेशन के लिए, और नया टर्म, और नयी देरी इस अच्छे काम में न हो सके। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय और सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी और कम्प्रेहेंसिव प्रोविजन्स सहित इस कानून को पास करवाने का इन्तजाम करेगी।

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सदन में बीड़ी और सिगार वर्कर्स का जो अमेंडमेंट बिल है उसके बारे में चर्चा हो रही है। यह बिल बहुत दिनों से पेंडिंग था अमेंडमेंट्स के लिए। प्रसन्नता है कि इस सेशन में यह आ गया और मुझे आशा है कि यह पास भी हो जाएगा। लेकिन गौर से अगर आप पूरे बिल को देखें शुरू से आखिर तक—इन अमेंडमेंट्स को जो मौजूद हैं, पेश हैं इनको भी दृष्टिगत करते हुए देखें तो जो बीड़ी वर्कर्स की कण्डीशंस हैं, हालत है, उनकी जो आवश्यकता है, सचमुच में, वास्तव में जो उनकी वर्किंग कण्डीशंस हैं, जिन स्थानों पर काम करते हैं, उनके काम करने का जो समय है, आवर्स हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है, इन सबको अगर दृष्टि में रखकर देखें बड़े पैमाने पर तो यह बिल, पूरा का पूरा जो कानून है यह अधूरा रह जाता है।

सोशल सिक्योरिटी—इंडियन कंस्ट्रीट्यूशन के मुताबिक, भारतीय संविधान के मुताबिक हमको जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीब, निर्धन, निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनके लिए डाइरेक्शन है कि उनके वेलफेयर में हमको वास्तव में दिलचस्पी लेनी चाहिए। आप देखें कि इसमें करीब-करीब 16 लाख के करीब आदमी बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं और 15 राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर यह काम होता है, और कुछ स्टेट्स में तो बड़े इन्टेंसिव तरीके से काम किया जाता है। इसके साथ-साथ जंगल से जो तेंदू लीफ है, बीड़ी का पत्ता जो होता है उसको इकट्ठा करने वाले भी

इसी धंधे से जुड़े रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यह जो बिल है यह सारी आवश्यकताओं, मांगों और उनके हालात को सुधारने की जो भावना है, कामना है उसको पूरा नहीं करता है। अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे वे बहुत अच्छे इंडीकेशन दे रहे थे। हमको एक सम्पूर्ण बिल ऐसा बनाने पर विचार करना चाहिए जो कि वास्तविकता में वह उनके जीवनायापन के लिए कल्याणकारी कानून हो।

आप गौर से जाकर देखें जहां ये बीड़ी बनाते हैं। बड़ी गंदी बस्तियां हैं जहां न पीने के पानी का प्रबंध होता है, गली-कूचे कीचड़ में पड़े रहते हैं। काम करने वालों के बच्चे वहीं खेलते रहते हैं। हेल्थी कंडीशंस नहीं होती हैं, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती हैं। ऐसी कंडीशंस में वे बेचारे बनाते हैं। दुर्भाग्य उपर से है कि जो इस कानून के मुताबिक हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह बने हैं वे उनकी उचित देखभाल नहीं करते बल्कि बीड़ी बनाने वाले जो मालिक हैं उनसे वे मिल जाते हैं। उनका जो काम है, जो उनकी ड्यूटीज हैं उनको भूल जाते हैं। प्रलोभन और लालचवश उस वर्ग को भूल जाते हैं जिसके लिए उनको नियुक्त किया जाता है अगर गौर से देखें तो जो मामूली वर्कर होता है वह एक तरह से बंधुआ मजदूर होता है। उनके पास पैसा नहीं होता है रोजाना की जिंदगी के लिए। रोज सामाजिक, व्यक्तिगत अपने जीवनयापन के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। नतीजा यह होता है कि वह बड़ा कमीशन देकर, पैसा कटाकर, सूद एडवांस कटाकर बीड़ी मालिकों से रुपया ले लेता है और उनकी बीड़ियां बनाकर पूरा करने का वायदा उनसे करता है। लिखित में देता है, रुपया उनसे दुगुना, तिगुना लिखवाते हैं। नतीजा यह है कि वह बीड़ी वर्कर—अगर गौर से स्टडी करें, सर्वे करें, कुछ लोगों ने किया भी है, उसका हवाला देने का वक्त मेरे पास नहीं है—तो देखेंगे कि हालत बंधुआ मजदूरों जैसी है। उनके उत्थान और उनकी उन्नति का ख्याल आप कर ही नहीं सकते हैं जब तक कि उनको आर्थिक तौर पर स्वतंत्र न करें। उनकी वेज पालिसी बनाई जरूर है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं उनकी जो शर्तें हैं काम करने की उसमें कह दिया कि तुमने बीड़ी अच्छी नहीं बनाई है और उनको पैसा नहीं देते हैं। दो-तीन रोज के बाद मालिक गुस्सा हो गया तो काम नहीं देगा। सौ पत्ते दिये थे, आपने चार पत्ते खराब कर दिये तो जिन पत्तों के लिए काम भी किया उनका पैसा नहीं देगा। इन सब चीजों को देखने के लिए आपने अधिकारी बनाया तो है, लेकिन वह अधिकारी उन मालिकों से मिल जाता है और उनका शोषण करने में और सहायता करता है। उसके लिए वाचडाग कौन होगा ? इतना बड़ा महकमा खड़ा नहीं किया जा सकता जितनी की आवश्यकता हो, लेकिन इसके लिए वाचडाग जो होना चाहिए, वह हमारे सोशल वर्कर्ज, जो जिले में, वहां के शहरों में जो लोग हैं, चाहे वह वालंटरी आर्गेनाइजेशंस के लोग हों, इस तरह के लोगों का भी इनवाल्वमेंट उनके कल्याण कार्य के साथ-साथ रहना चाहिए। अकेले इंसपैक्टर पर या किसी अधिकारी पर छोड़ देना, यह मेरी समझ में उचित नहीं लगता है और उससे कानून का मंशा भी पूरा नहीं होता। बल्कि कांग्रेस सरकार की जो नीति है, जो उसका इंप्लिमेंटेशन का काम है, जो उनको लोन दिलाये जाने का काम भी है, उसके मुताबिक भी उनको नहीं मिलने देते।

मालिक यह शर्त कर देता है और यही नहीं जिस मालिक की वह बीड़ी बनाता है, वह कह देता है कि आप दो साल तक या चार साल तक मेरे अलावा और किसी की बीड़ी नहीं बनायेंगे यहां उनके काम करने की आजादी भी छिन जाती है। जैसे हमारे

संविधान में लिखा है कि जहां आपका मन चाहे, वहां काम करिए, जिसके यहां दिल चाहे, उसके यहां रोजगार कीजिए, उसकी नौकरी कीजिए, अपनी स्वतंत्रता से काम-धंधा करने की छूट है। लेकिन वहां पर आप प्रैक्टिकली जाकर देखें, इनकी उन बस्तियों में देखें, उनसे मिलें और रिए-लाइज करें, उनकी जानकारी करें, रिसर्च करें, तो आप देखेंगे कि उनके हालात ये हैं कि वह बाकायदा लिख में लिखवाते हैं कि मैं आपको बीड़ी बनाने के लिए अपने यहां रखता हूं, लेकिन आप चार साल तक मेरे यहां ही रहेंगे, किसी और के पास नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे, तो इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, यह भी बाकायदा स्टाम्प पेपर पर करवाते हैं।

यह तो अठारहवीं सदी के कानून का प्रचलन मालूम होता है। तो मैं चाहता यह हूं कि इसके लिए सरकार की ओर से कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए, जोकि इन सब चीजों को देख कर, बड़े पैमाने पर स्टडी करके, उनके बीच में रह करके, देख करके, जान-कारी करके, दो-चार हफ्ते वहां रहें और एक अच्छा नियम, साधन बना कर लायें, तब यह हो सकता है।

अब आधे से ज्यादा बच्चे और औरतें, जो बीड़ी बनाते हैं, वह कैंसर के मरीज होते हैं, क्योंकि यह तंबाकू तो खुद ही कैंसर पैदा करने वाला है। इसमें निकोटीन होती है, जो दमे की बीमारी करती है और निकोटीन से सब से बड़ा नुकसान यह होता है कि उससे अंगुलियां गल जाती हैं।

मिल मालिकों को या सरकार को कोई ऐसी चीज निकालनी चाहिए बीड़ी बनाने वालों के लिए साइंटिस्ट लोगों से कहें, एक्सपर्ट्स से कहें कि कोई ऐसा दस्ताना या कोई चीज निकालें, जिसको पहन करके, जैसे डाक्टरों के पास बड़े-बड़े पतले दस्ताने होते हैं, जिसे पहन कर वह संग-संग बीड़ी बनाते रहें। हमने देखा कि बहुत से बच्चे जो बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनकी अंगुली आधी गायब है, कटी हुई हैं। निकोटीन की जो एसिडिटी होती है, वह सब काट देती है।

तो हैल्थ में उनको जीवित रखना, उनको तंदरुस्त बनाना तो दूर रहा, बल्कि जो काम करते हैं बहुत से, उनकी अंगुलियां खराब हो जाती हैं। इन सब चीजों का उपाय करने की बड़ी आवश्यकता है।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार कोई कमेटी बनाये, इनडेप्थ स्टडी करे। बीड़ी मालिक तो कुछ काम नहीं करते, वह सिर्फ तो उसे बेचने का, व्यापार का काम करता है। आपके जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, वहां पर सब जगह बोनस का सिस्टम है। आप प्राफिट से कुछ न कुछ शेयर—इस तरह से सरकार भी बोनस देने लगी है। बैंकों में भी हर जगह कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में वह रुपया मिल जाता है।

तो, मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि यह सारी जो बीड़ी बनाने की जिनकी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं और वह बड़ी रकम वाले, बड़े मालदार होते हैं, इनका इतना बड़ा बिजनेस सारे देश में चलता है। तो, मान्य-वर, मेरा आपसे यह आग्रह है कि 25 प्रति-शत उनका बोनस तय कर दें, जो बीड़ी मालिक हैं, उनके यहां से कितने की बिक्री हुई, कितने का माल गया, वह सारा हिसाब करने के बाद 25 प्रतिशत बोनस, जो उनके बीड़ी वर्कर्ज हैं, जो बीड़ी बनाने वाले हैं, बच्चे और स्त्री-पुरुष, उनको दे देना चाहिए, एनुअली या छिमाही या तिमाही, यह सब तय करने के लिए कानून की बहुत आवश्यकता है। वरना, उनका जीवन तो ऐसा है, जैसा समझिये जैसा होता है ना, स्लो सूसाईड कर रहा है आदमी।

तो इन कंडिशंस के सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। सब से बड़ी बात मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि किसी भी बीड़ी बनाने वाले मालिक को तब तक बीड़ी बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए जब तक कि उसके पास हैल्थी वातावरण वाला कोई साफ-सुथरी जगह वर्कर्ज के लिए नहीं है। वह नाली के किनारे सड़ी-गली जगह, जहां पर आदमी जिन्दा नहीं रह सकता, कीचड़ में बैठे हुए हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, अंबार लगे हुए हैं, चले जाइये गंदे से गंदा कूड़ा पड़ा हुआ है, वे बेचारे बीड़ी बनाते रहते हैं और मालिक आकर देखता रहता है।

तो, मान्यवर, मेरा यह भी आग्रह है कि इसमें अगर बीड़ी बनाने का कोई लाइसेंस होता हो, या अगर नहीं है, तो ऐसे आदमी को तब तक बीड़ी बनाने का हक नहीं होना चाहिए, या बेचने का हक, या सप्लाई करने का हक नहीं होना चाहिए जब तक कि वह बीड़ी वर्कर्ज के लिए साफ जगह, जिसमें बैठ कर वह बीड़ी बना सके और वहां उसके लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी हो, हैल्थी वातावरण हो। यह सब जब तक नहीं हो, आपको किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो मान्यवर, यही मेरे विचार थे। इस संबंध में मैं फिर माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इन-डैप्थ स्टडी करा लें और इनके वैलफेयर के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I come from the State of Orissa and I know how powerful the tendu leaf traders are. In the 'fifties' and 'sixties' and even in the 'seventies' they were so powerful. The tendu leaf traders were behind the making and unmaking of even Governments also. Those who actually make the beedis are the very poor people and the Minister has himself admitted that a large number of people are engaged in making beedis. The previous speakers have already stated that they work under unhealthy and pitiable conditions and they are exploited by the employers or the *thekedars*, whatever you call them. From the outside we will find that the beedi workers are independent workers. But actually they are not. They are always exploited by the employers or the *thekedars*. So far there is not a single comprehensive Central law covering all aspects of the beedi industry, particularly the workers. The law which was enacted in 1966, that is, the Beedi and Cigar Workers Act, did not differentiate the home-made beedi workers and the factory workers and the State Government's power was also not accepted by some of the employers and the Government had to bow down before those employers. The provisions of various Central laws applicable to the workers are not strictly implemented and the facilities envisaged thereunder are not actually extended to them. The laws enacted at different times for the beedi and cigar workers have not given any benefit to the workers. Generally the law-makers and those incharge of implementing the laws are in collusion with the employers. They accept corrupt methods and I am afraid that the present Act and the present amendment may not help the workers because the same think will happen. The employers with the connivance of the inspectors behave the same way as they had done to the workers earlier.

In most of the places the beedi workers are women and they are always exploited. They are not given the benefits of the maternity benefit scheme although the provisions of the scheme are applicable to them. They are exploited. They are not given equal wages. They are not treated

on par with men. Women workers have to work throughout the day. They have to sit with tobacco. Tobacco is very hazardous to health. They have not been given proper health care and adequate and specialised medical facilities are not provided to them. Sometimes they are not in a position to get pure drinking water. I have visited some of the colonies of beedi workers in Karnataka and I have personally seen the conditions in their colonies. They are in unhealthy conditions. If the Minister wants to make some law, it is not going to help. If he wants to help the workers, he has to take some welfare measures which will actually help the workers. I congratulate the Minister on bringing this amendment. But at the same time, as I said earlier, it may not be helpful to the workers. I would like to give some suggestions for the welfare of the beedi and cigar workers. First, promote and strengthen the cooperative movement among them. They are unorganised. They should be organised. They should be given housing loan and other benefits also. They should be given the benefit of Provident Fund scheme. At some places this facility is available. But they are not given proper facilities to utilise the Provident Fund Scheme.

The second is proper utilisation of beedi workers' welfare fund. The welfare fund is not properly utilised. As I said earlier, they should be given housing loan so that they can have their own house. My third suggestion is, stop the exploitation of child labour. The previous speaker also said that children are being exploited. Yesterday also we discussed child labour. Sir, most of the workers are children. Whatever amount is given to them they accept it. Then employers are also interested in getting child labour. They don't have the insurance scheme also. Some help should be provided to the aged workers who are not in a position to work. Some provision should be therefor the aged workers under which they can get help from the employer or from the Government. I would like to tell the Minister that if the Government is actually interested to help the workers, the Government should strictly implement the law and find out whether the law is actually in a position to help the poor workers.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं इजाजत चाहता हूं अपनी सीट से आगे आकर बोलने की।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1990 जो इस माननीय सदन में प्रस्तुत है, इसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक को लाने में मंत्री जी की जो भावना रही है, वह बहुत अच्छी है। एक ऐसे तबके के लोगों के लिए, जो सबसे नीचे के स्तर का तबका है और जो बीड़ी मजदूर का कार्य कर रहे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं, उनके लिए और उनके कार्य में आने वाली जो दिक्कतें हैं, जो बीड़ी बनवाने वाले ठेकेदारों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन दिक्कतों को दूर करने से संबंधित यह जो भावना मंत्री जी की है, उसी भावना से यह विधेयक लाया गया है। इसलिए मैं इसका स्वागत कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस देश के अंदर बीड़ी और सिगार मजदूर जो हैं, उनको दैनिक वेतन किसी स्थान पर 12/- रुपए से 14/- रुपए और किसी स्थान पर 4/- रुपए से 5/- रुपए मिलता है। इन मजदूरों के वेतन में एकरूपता भी जरूरी है। इसके साथ ही बीड़ी मजदूरों के लिए जो ठेकेदारी प्रथा है, इसके लिए मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करें और मजदूरों की एक सहकारी समिति बनाकर सहकारिता के माध्यम से बीड़ी उद्योग को चलाया जाना

चाहिए, जिससे निश्चित रूप में बीड़ी मजदूरों को विशेष लाभ हो सकेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कई बार यह चर्चा भी आई है कि बीड़ी मजदूरों की बीमा योजना को लागू किया जाए। इस विधेयक में बीड़ी मजदूरों के लिए बीमा योजना लागू करने की बात को और जोड़ दिया जाए, जिससे उन कर्मकारों का भला हो सके। इससे निश्चित रूप से उनको, उनके परिवार को जीवन पर्यन्त एक रास्ता मिल सकेगा।

अन्त में, मैं यही कहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से जो अधिकार आप दे रहे हैं और जो कुछ प्रशासनिक या व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थीं उनको दूर करने के लिए जो आप इसमें संशोधन लाए हैं, मैं समझता हूं कि यह संशोधन विधेयक अच्छा है और इससे कुछ राहत तो बीड़ी मजदूरों को जरूर मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जयहिन्द।

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, the Bill is very important to several lakhs of unorganised workers working in Beedi and Cigar industries and also to the lot of workers who work on the farms which is also related. The Bill was prepared in 1990 and somehow it was not passed. Now, almost after more than 3 years we are going to adopt it. Even then the Government did not utilise the time it got to improve upon the Bill. The Government did not make the best use of that time. I will draw the attention of the Government to some of the clauses in the amendment Bill which I think should have been further amended during this time. For example, in clause (hh) on page 2 of the amendment Bill, 'godown' has been defined. But about the workplace of the beedi workers, most of whom are women who prepare or manufacture beedi in their houses, nothing has been said in this amendment Bill. These unfortunate women are deprived of all legal benefits, whatever little that is there. Next, I would like to draw the attention of the Government to a peculiar amendment in clause 7A (i) of the amendment Bill. It has been said that no inspector shall disclose the name of the person who has made the complaint. It is to protect the workers from the wrath of the employers that the inspectors have been directed not to disclose the name of the complainants. In the next paragraph, it has been added that if the person concerned does not object, then his name can be disclosed. I think that this is not proper in view of the situation that prevails in the country and which has made the Government to bring this amendment. I think that this aspect should be taken note of and the Bill should be amended accordingly. The next thing is, the Government has provided an explanation in the existing clause wherein the *modus operandi* of computing overtime wages has been defined. Here, it has been said in the original clause that even the workers employed on a piece-rate basis will get their overtime on a time-rate basis. Now, this has been a longstanding dispute in the workers' movement whether the piece-rate workers and the time-rate workers are getting the same benefit or not. Here also, there should be a legislation over the *modus operandi* of finding out as to what is the exact amount and whether the workers are getting the exact amount. In an organised industry, the workers are opting for the time-rate wage payment instead of the piece-rate one. This is more so in the coal industry. I think that this aspect should be taken note of before the finalisation of the Bill. So, at this stage, if the Bill is not amended further and the Government assures us that it will be amended, I think that it will not be able to serve the purpose. Our country has a large number of unorganised workers, especially, women and children. There is no health

service provided for them and there is also no organised trade union movement. They are to depend on the good and bad wishes of the employers. So, I think that there must be a proper organisation for the workers in which they can have their own representatives and defend their cases. Now, the next question that arises is the provision of health services for the workers. Now, there is no organisation. There is no ESI facility separately for them and as the industry is spread all over the country, it will be very difficult to give them the redress and ask them to go to that place. These workers suffer from all sorts of industrial diseases, and especially, tuberculosis. There are other diseases which the workers are prone to especially because of the hand-rolling of the beedis. This aspect should be taken care of and in consultation with the panchayats, the health services for these beedi workers and the rural workers, agricultural or quasi-agricultural workers, should be provided in the rural areas. Where there are big manufacturing centres and where mechanisation is advanced, the problem may be different and it will be easier to provide health services through the organised systems. I think that if the Government takes care of all these things, then the Government's intention will be fruitful. Unless it is done, the Bill will come and go but the workers will remain in the same darkness and realm of exploitation.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Shri Shanti Tyagi, not here. Shri Ish Dutt Yadav, not present, Shri Giri Prasad.

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I support this Bill to the extent it goes. You know beedi workers in our country are in large numbers, almost twice the number of the public sector workers. So far as my information goes, there are 50 lakh beedi and cigar workers in the country. Though the Government is bound to implement the labour laws, it is unable to implement even the minimum things. For example, all the beedi workers are supposed to get identity cards. According to our information, only about 25 lakh beedi workers were given such identity cards. Then what happens to the remaining 25 lakhs ? Whose responsibility is this ? Why is the Government keeping mum on this aspect ? Why is it not pressurising the State Governments to implement even this minimum things ? Unless you identify the actual workers, how can you provide the minimum facilities and implement the labour laws or the welfare measures ? So, I would ask the Minister to kindly look into this aspect and take speedy steps to identify them, issue identity cards to the remaining 50 per cent workers and take necessary steps for the amelioration of their difficulties.

Sir, the second thing is that the main aim of the Government should be to cooperativise the sector. Unless they are brought into cooperative basis, the real benefits cannot accrue to them. But in the immediate future, it would not be possible to cooperativise all the beedi workers; it may take some time. There is one example in Kerala. One Dinesh Co-operative Society is there in Kerala and they are able to give Rs. 30/- per day as a minimum wage whereas in other States where these beedi workers are employed by the private manufacturers and others, they are giving them around Rs. 20/- per day or even less than that. So, there is an element of exploitation of these beedi workers. Some better wages can be given.

Moreover, the procurement of tendu leaves should be monopolised by the Government and they should supply to the manufacturers directly. Then the intermediaries and middlemen will go and some money can also be saved. According to a

study—I request the Minister to go through this aspect—if a minimum amount of Rs. 350/- is spent on a worker, either through cooperativisation or through some other welfare measures, then they will be able to earn an income of Rs. 1,150/-. This is according to one study. If that is so, the Government's excise income will also increase. Now, according to a study, they are getting Rs. 100 crores on this account and this will also go up. Not only do the workers get benefited, their incomes go up, but the Government's income will also go up. So, all these aspects must be kept in mind. The other worrying problem is that of child labour and it is a case of bonded labour and especially in some States this has become a legal method of employing children on the basis of bondage. I think it is against all civilized methods and the Government should not encourage this thing. Of course, the poor people have to do this because this arises out of poverty and they have no other means of earning their livelihood. Naturally, the poor parents send their children for making beedis. It is a home industry and the contractors and the manufacturers will give some tendu leaves or tobacco to make beedis. I have seen personally that in many families, both children and the womenfolk work together prepare these beedis. But the main problem before the Government and the nation is to make these children go to schools and it is the responsibility of the Government to introduce compulsory education up to the age of 14 years. Only when it is so, you would be able to fulfil the Directive Principle enshrined in the Constitution and make every citizen a literate person. So, the Government should discourage the children being employed in this sector. Also, by increasing the income of the parents these children can be liberated. The manufacturers or the contractors, whoever they may be, are charging very exorbitant rates of interest and that is why the bonded labour system continues. So, unless the Government takes some steps to eliminate this bondage and liberate these people and allow these children to go to schools, their conditions will not improve. There is a provision also for a cess, I am told. If that cess is collected properly from all the manufacturers, that money can be used to educate these children.

Lastly, there is a Supreme Court judgment of 1991 according to which the Government has to undertake certain measures, especially the extension of the Employees' Provident Fund Act and also life insurance cover up to fifty thousand rupees per worker. The Government must consider all these things. Otherwise the conditions of these beedi workers, of whom there are lakhs and lakhs, will not improve at all.

There is a great demand from these beedi workers for housing facilities. Mostly these beedi workers come from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and backward classes and most of them belong to the oppressed and the downtrodden sections of the society. Naturally, they do not have their own houses. If you go to their houses, you will see that they have to live and work in the same hut preparing beedis. Health Hazards are also there. That is why I request the Govt. to insist upon the manufacturers, especially the big ones, providing houses or house sites. The Government also, with its own resources, must come forward to build houses for these people.

Then, even the statutory minimum wages are not being paid in some States and provisions are not implemented in the Northern States. There is a difference between branded and unbranded beedis and the Government is losing a lot of revenue by exempting these unbranded beedis from excise duty and other things. I would, therefore, request the Government to appoint a Commission to study all these as-

pects in order both to get proper income for itself and also to see that the living conditions of these lakhs and lakhs of beedi workers are improved.

I hope the honourable Minister will give some thought to these problems and do certain things even going beyond the purview of this Bill. Thank you, Sir.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh) : Sir, my friend, Shri Giri Prasad, has dealt with the subject in an extensive way. I would only like to add two more sentences apart from what he has said.

It is surprising that the highest income-tax payer in the country is the beedi manufacturer. There is a lot of money in beedi and cigarettes. But the money which is generated in this industry is not going to the manufacturer; not even a trickle is going to the actual beedi manufacturer.

Sir, this Beedi leaf is grown in a forest. Naturally, it belongs to the Girijans. Traditionally, for hundreds of years, the Girijans living in those areas use to collect these Beedi leaves and then sell them to outsiders, to the people from the plains. After some time, the State Governments had come into the picture, and they started auctioning the leaves and they started realising some money by way of auctioning these Beedi leaves. Then the contractors had come into the picture. Now, the entire money generated in this Beedi industry is being pocketed by the contractor, by the manufacturer and by the manipulator who would be able to manage both the State Governments and the Central Government as well as the industry people.

Sir, I have been following the various Budgets presented by the Central Government. The Government of India is taxing heavily the cigarette-smoking, but they are not taxing that much the Beedi and the Cigar. Taxation is very less with regard to Beedis and Cigars because they are being consumed by the poorer sections of the people. Though the reasoning of the Central Governmnt is that taxation should not be heavy and that they should not be harsh on Beedis and Cigars because they are consumed by the poorer sections, I have my own doubts. The Government of India may be interested in the health of the people who smoke high quality and high-priced cigars. But I am not convinced that they are interested in the health of the people who smoke these Beedis. Whatever that may be, Sir, I have no quarrel with the Bill brought forward by the Minister. But this Bill is not sufficient. I am quite certain that there is tremendous exploitation going on at the level of the manufacture of Beedis. As Mr. Sangma has stated, most of the people involved in this industry belong to the poorers sections, the Scheduled Castes and the tribals and the other backward classes. So far, no State Govt. or for that matter, the Central Govt. could be able to provide or evolve any welfare scheme which will be of some use, some help to these people. Not only that. The existing laws are also not being implemented. As far as minimum wages are concerned, there is no supervisory mechanism either with the State Govts. or the Central Govt. to see that the legislation on minimum wages, enacted by the various State Governments and the Central Government is implemented. As my friend has just now stated, there is bonded labour going on in this industry on a large scale. Mostly children are involved in this Beedi manufacture, and nobody has come to their rescue. There are no educational facilities, there are no health facilities, and not even a single welfare measure to benefit these unfortunate children. So, I request the Minister that he should not merely be satisfied with the existing amendments to the Act. They should appoint a Committee, as suggested

by my friend, a Committee of experts or a Committee of Parliamentarians or a Committee of people who are actually working in these tribal areas for the upliftment of these tribals. Let that Committee go into the living conditions of these Beedi and Cigar workers and let there be a comprehensive legislation. The objective should be the welfare of those people who have been involved in this industry. Thank you, Sir.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (Nominated) : Sir, I am going to harp on only two points regarding this Bill. Sir, I would like to draw the attention of the Minister to the report submitted by the National Commission on Women. And they have brought out the plight of the women beedi workers which consists of nearly 50 per cent of the beedi workers in total. One of the instances in which the beedi worker is deprived of his wages is that the contractor or the employer gives them lesser quantity of raw material, say, to roll one thousand beedis, and when the worker brings back the beedis after manufacture, the contractor would say : "We have given you this much quantity of tobacco and leaves and you have not supplied the required one thousand beedis." In fact, as I said, the raw material required for making one thousand beedis is not issued in full quantity. A lesser quantity is given. The result is that there is a cut in the wages of the worker in the name of supplying lesser number of beedis. This is one way in which the worker is deprived of his full wages. I would like the hon. Minister to look into this aspect and provide protection to the workers. Then the other instance is that the contractor or the employer normally goes in for a system in which they make a cut of 20 per cent of the total number of beedis manufactured by the worker saying that 20 per cent of them have not been properly rolled, and under that excuse or some other excuse, the wages of the worker are reduced by 20 per cent. So, this is another way by which the worker is exploited. I do not find any mention anywhere whether the State Government or the Inspectors appointed under the Central law would be able to provide any protection to the workers against this exploitation.

Next issue connected with this is about the *tendu pattas*. To save themselves from such exploitations, some workers have sought to form their co-operative society. Now, *tendu patta* transaction is a State subject. Some of the State Governments have gone in for nationalisation of the whole process and in some States, it is still in the hands of private traders. Wherever a co-operative society is formed by the workers, these private traders see to it that the co-operative society is deprived of the *tendu patta* so that they do not get these leaves in sufficient quantity required to roll the beedis, and slowly and slowly, these co-operative societies would be phased out. I request the hon. Minister to see if he can come out with a legislation or whether he can ask the State Governments to take over the transaction of the *tendu patta* which is in the hands of traders, and give it to the regular forests department. A study was made and a report was submitted to the Government of Madhya Pradesh where it was said that the transaction in *tendu patta* alone was of the order of Rs. 900 crores. By leaving this business totally in the hands of private traders, there are many illegal activities going on. The legitimate rights of beedi workers who are also *tendu patta* collectors are not being protected and I would like the hon. Minister to look into it.

The last point I would like to make here is this legislation which has been brought

forward is not being applied universally, is not being made applicable to all the States. We have left it to the sweet will of the States themselves.

Let me give one eaxmple. In the last Budget which was presented by the Govt. of Maharashtra before the Legislative Assembly, they raised the excise duty by 15 per cent. The consequences is that the industry in the districts of Chandrapur, Bhandara and Gadchiroli, surrounding Madhya Pradesh, shifted to Madhya Pradesh where there is no such excise duty. As a result of this, the workers in these districts are deprived of their work. The number of workers involved is 7-8 lakhs. The workers have been deprived of their work. The industry has totally collapsed. The industry has been closed. Since the industry has been closed, these people are living from hand to mouth there today. May I, therefore, ask the hon. Minister whether, instead of leaving it to the sweet will of the State Governments, he would make it applicable to all the States and ask the State Governments to implement it? Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Sangh Priya Gautam. Only three minutes.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सिवाय मंत्रियों को छोड़ कर कांग्रेस पार्टी का एक भी सदस्य इस समय यहां नहीं बैठा हुआ है । इतनी उनको चिन्ता है देश की । उपसभापति महोदय, मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि बीड़ी, सिगार और सिगरेट का उत्पादन और उपभोग बिलकुल बंद होना चाहिये । बीड़ी सिगरेट से कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि है । न तो यह विदेशों में भेजी जाती है और न इससे विदेशी मुद्रा कमाई जाती है । बीड़ी सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । यह बिलकुल सही लिखा रहता है । बीड़ी पीने वालों की होंठ काले हो जाते हैं, मुंह से बदबू आती है और फेफड़े जल जाते हैं । पैसे की बरबादी होती है । कपड़े जल जाते हैं । घर में गरीब लोग कई कई बंडल बीड़ियां पीते हैं जिससे हजारों रुपया महीना बीड़ी पीने में चला जाता है । यह विधेयक ला तो रहे हैं उनके कल्याण के लिए लेकिन बीड़ी-सिगरेट से, सिगार से जितना नुकसान इन गरीबों का हो रहा है इतना किसी और का नहीं हुआ । मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप मुझ को दो मिनट और दे दीजिये । एक आदमी पंजा छाप बीड़ी बेच रहा था, कांग्रेजी पंजा नहीं । वह यह कह रहा था कि मेरी बीड़ी पीने वालों को तीन फायदे होंगे । उसने कहा कि मेरी बीड़ी पीने वालों को कुत्ता कभी नहीं काटेगा, मेरी बीड़ी पीने वालों के घर में कभी चोरी नहीं होगी और मेरी बीड़ी पीने वाला कभी बुड्ढा नहीं होगा । मुझ जैसा एक आदमी उससे जा भिड़ा और उससे कहा कि पहले इसका मतलब मुझको समझाओ नहीं तो तुम्हारी बीड़ी मैं नहीं बिकने दूंगा । तो वह बोला कि देखो मेरी बीड़ी पीते पीते उसको खांसी हो जाएगी और खांसी हो जाने से उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे। फेफड़े खराब हो जाएंगे तो वह टी. बी. का मरीज हो जाएगा । जब टी. बी. का मरीज हो जाएगा तो बगैर लाठी के सहारे चल नहीं सकेगा । लाठी के सहारे चलेगा तो लाठी को देखकर कुत्ता नजदीक नहीं आएगा । जब कुत्ता नजदीक नहीं आएगा तो कैसे काटेगा कुत्ता ? दूसरा यह कि मेरी बीड़ी पीने वाला रात भर खांसता रहेगा । खांसी के कारण वह सारी रात जागता रहेगा । उसकी खांसने की आवाज सुनकर चोर समझेगा कि वह जाग रहा है। इसलिए चोर उसके घर में नहीं घुसेगा । उसने कहा दो बातें तो समझ में आ गईं

अब तीसरी बात बताओ कि वह बुड्ढा कैसे नहीं होगा। उसने कहा कि तू बिलकुल बेवकूफ है । जब उसको जवानी में ही टी. बी. हो जाएगी तो वह जवानी में ही मर जाएगा, उसके बुड्ढा होने का नम्बर कहां आएगा ? मान्यवर, इसलिए मैं यह कहता हूं कि बीड़ी के उत्पादन और उपभोग पर पूरी पाबंदी होनी चाहिये । लेकिन हमारे देश की परम्परा बड़ी विपरीत है । यहां पर बुरे कर्म को भी आमदनी और पैसे से जोड़ लेते हैं । चूनांचे यह परम्परा बन गई है । बहुत से लोगों का जीवन इससे जुड़ गया है । जितनी बीड़ी बनती है, तम्बाकू पैदा होता है लिहाजा किसान की जिन्दगी जुड़ गई है । पैसे वाले पैसा पैदा करते हैं, पूंजीपतियों की जिन्दगी जुड़ गई है । सरकार को रेवेन्यु मिलता है, सरकार की जिन्दगी जुड़ गई है । कहते हैं कि गरीबों का कल्याण होता है, रोजी-रोटी मिलती है, सही यह है कि गरीबों का नाश होता है । मैं लम्बी बात न कह कर मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब मैं कहता हूं तो अपने मन की बात कहता हूं । रब्दा गंजे को नाखुन दे दे, कहीं मैं पावर में आ गया और मिनिस्टर बन गया तो मैं तो स्मोकिंग बन्द कर दूंगा चाहे मुझे दूसरे दिन जाना पड़े, मैं रहूं या न रहूं, केयर दे्यर इज ए विल, दे्यर इज ए वे । मगर मैं गरीबों के कल्याण के लिए तीन चार सुझाव देना चाहता हूं । नम्बर एक, यह जो पत्ती है जिससे बीड़ी बनती है, आदिवासियों की यह तेंदू लीफ उनकी अपनी सम्पत्ति थी मध्य प्रदेश के अंदर और बगैर किसी पैसे के लाते थे तोड़ करके । उनका यह राइट उनको वापस दे दीजिए, फिर दे दीजिए । यह देश का कल्याण होगा । एण्ड अवर्स इज ए वेल्फेयर स्टेट, आप अगर इनका कल्याण करना चाहते हैं तो । तम्बाकू अलग दें । पत्ती अलग काटकर लायें । पत्ती काटने वाले अलग अलग पत्तियां काटें, तम्बाकू अलग भरें ताकि उनका शोषण न हो।

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : आपकी पार्टी की सरकार ने ही तो उनको जो अधिकार दिया था फिर से वापस ले लिया ।

श्री संघ प्रिय गौतम : वह तो आपने वापस ले लिया । आप उनके आदिवासियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप ही उनका शोषण करा रहे हैं । अगर मैं होता आपकी जगह तो यह कभी न होने देता ।

श्री अजीत जोगी : चार सौ करोड़ रुपया साल का मुनाफा उनका हुआ था . . . (**व्यवधान**) आपकी सरकार ने ही उनके इस अधिकार को वापस ले लिया ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं शराब और नशीली चीजों के उपयोग और उत्पादन के सख्त खिलाफ हूं चाहे कितनी ही आमदनी क्यों न हो . . (**समय की घंटी**) मान्यवर लास्ट में एक सुझाव दे रहा हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Your party's five minutes are over.

श्री संघ प्रिय गौतम : पत्ती और तम्बाकू के अलग अलग काम होते । पत्ता देते हैं गोला। वह सूखकर अगर वजन में कम हो जाता है तो उससे कहते हैं तुमने चोरी कर ली पत्ते की, उनका पैसा काट लेते हैं मजदूरी का, और आगे के पैसे काट लेते हैं । वैसे पत्ता काट-छांट में भी निकल जाता है । एक तो यह मेरा सुझाव है । दूसरा जिस तरह से टेनरीज हैं और गांवों में बहुत से लोग टैनर होते हैं लेकिन बदबू की वजह से टैनरी अलग बनाई जाती है । ठीक इसी प्रकार जहां पर घरों में ज्यादा बीड़ी कर्मकार लोग काम करते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से एक दाउंड्री वाला कोई हाउस अलग बना दिया जाए जो उनका डवेलिंग हाउस न हो और मान्यवर अब उनके लिए वहीं पर हर प्रकार की व्यवस्था होगी . . . (**समय की घंटी**) लास्ट एक सुझाव है । यह कर दीजिए । वैसे अभी डेढ़ घंटा इसके

लिए टाइम था सर । डेढ़ घंटा अलाट हुआ था, अभी एक ही घंटा हुआ है, हाफ एन आवर इज स्टिल लेफ्ट । मैं एक मिनट में ही निवेदन कर रहा हूं । उनके बच्चों के लिए वहां स्कूल की व्यवस्था हो, दवाखाने की, दवा की व्यवस्था हो । दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं सर कि जिनके बच्चे हैं उनके घरों में बीड़ी न बनाई जाए । आप कहते हैं कि बच्चे काम न करें । रोज हम चिल्लाते हैं । श्रीमन्, घर में बीड़ी बनेगी तो बच्चे जरूर काम करेंगे इसलिये **(समय की घंटी)** एक मिनट

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Kindly conclude. You have taken more than 7 minutes.

श्री संघ प्रिय गौतम : घर में बीड़ी नहीं बननी चाहिए । घर से बाहर एक हाउस हो ताकि बच्चे जा ही न सकें और जाएं तो आइडेंटीफाई हो जाएं । इंस्पेक्टर जब सौके पर जाए तो देख ले । घरों में जाकर क्या देख सकता है कि बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं । मैं आपको यह सुझाव दे रहा हूं । इसलिए अलग उनका बिजिनेस होना चाहिए ताकि ये आइडेंटीफाई हो जाएं और चौथी बात उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वेजेज जो हैं उनके वे न्यूनतम तो हैं ही । ये इंप्लीमेंट होते ही नहीं हैं । आपने कहा कि प्रशासनिक और व्यवहारिक कठिनाई है . . . **(व्यवधान)** क्या कठिनाई है ? कठिनाई कोई हल करना ही नहीं चाहता है उन्हें देना ही नहीं चाहता है। आपने कभी इस मामले में, जो न्यूनतम वेजेज नहीं देते हैं उसमें कितने लोगों को आज तक अरेस्ट करवाया, उनका चालान करवाया . . . **(समय की घंटी)** It is a criminal offence. I am a lawyer, I know it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Now, please conclude.

श्री संघ प्रिय गौतम : लास्ट सर । लास्ट सुझाव मेरा है । अब ये जो ठेकेदार हैं, ये एजेंट आपने बीच में जाहे को पाले हैं । को-आपरेटिव सोसायटी इन्हीं मजदूरों की, जो बीड़ी के कर्मकार हैं इन्हीं की बना दीजिए । ये तो खुद ही बनाते हैं तो इन्हीं की को-आपरेटिव सोसायटी हो जाएगी । डाइरेक्ट ले लें मालिक से तम्बाकू और पत्ती वहां से लायें । बनाकर बीड़ी उसको दें । ये एजेंट शोषण करने वाले बीच में काहे को हैं । माफ करना, यहां पर हर चीज राजनीति से जुड़ गयी है । यहां पर वोट पाने के लिए एजेंट चाहिए, कमीशन खाने के लिए एजेंट चाहिए, देश के भले की चिंता बहुत कम लोगों को है । मंत्री जी आप अच्छे मंत्री हो और होशियार भी हो . . . **(व्यवधान)** मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं । सिक्का का राज एक दिन के लिए हुआ था, चमड़े का सिक्का चला दिया था तो आप चमड़े का सिक्का चलाइये अगर हित चाहते हैं इन मजदूरों का । तो आपको मैंने तीन-चार सुझाव दिये हैं । उपसभाध्यक्ष जी की कृपा है कि मुझको टाइम दे दिया । मगर थोड़ा सा टाइम्स और देते, तो और सुझाव दे देता । आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।

SHRI P. A. SANGMA : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to all the hon. Members who have participated in this debate for supporting this Bill. I do not want to waste the time of the House by repeating again the purpose of the Amendment. It has by and large the approval of the whole House except my good friend, Mr. Gautam, who says that the manufacture of beedi and cigars should be stopped completely. We can do it provided you take the responsibility of giving employment to 5 milion beedi workers in this country and millions of farmers in Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra. So, it is not an easy thing to say that this should be done and that should be done.

Anyway, Sir, we have almost 5 million beedi workers. Five million families are

dependent on the manufacture of beedis. It has been a consistent endeavour, attempt on the part of the Government to give them the maximum benefit in terms of working conditions, in terms of minimum wages, in terms of welfare measures, but there are problems connected with all these activities.

The most important problem that confronts us is the identification of the beedi worker and the establishment of the relationship between the employer and employee. You are aware that it is only a small percentage of beedis, which is manufactured by factories. The major production of beedis is manufactured at home on a piece-rate basis. Normally it is done through contractors. Therefore, it becomes very difficult to establish the relationship between the employer and the employee because in between we have these contractors, and that is the reason why most of the benefits cannot reach the beedi workers. Therefore, Sir, it has been our utmost attempt to see that we identify the beedi workers, and we issue identity cards. As the hon. Member has pointed out, unfortunately, out of 44.72 lakh beedi workers estimated, we have been able to give identity cards only to 25.85 lakh workers. I find that the progress of issuing identity cards has not been very satisfactory in the northern and the eastern parts of India. In the southern part of India it has been quite well, including the coverage of the provident fund. In the southern part and the western part of India they have done very well. I must congratulate the State Governments for that, for helping us. But, somehow or other, in the northern part of India and the eastern part of India, the progress has been very small. However we are trying our best. Recently we have given the power of issuing of the identity cards to the Medical officers of dispensaries under Labour Welfare Organizations and that is how we are seeing some progress now.

A lot of points have been raised regarding the welfare and healthcare activities and rightly so. At the moment we have two hospitals, 50-bedded hospitals for beedi workers. Two more hospitals are under construction. We have got one chest Clinic and 154 dispensaries spread out in different parts of India. So, it is not a fact that we are not doing anything as far as the beedi workers are concerned. We are doing something. I do agree, with the hon. Members that it is not enough and that something more needs to be done.

The second area which has been emphasised in this debate is regarding the housing programme. I think it is very important, and I do agree, that it should be one of the major activities in the field of welfare schemes for the beedi workers. As of today we have sanctioned more than 20,000 houses for construction under housing scheme for economically weaker sections of beedi workers and most of them are in Karnataka and Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh we have sanctioned 9064 houses, 3300 of them in Nizamabad. I am going to visit that place. In Maharashtra some years ago there was a very good programme. In Sholapur we have constructed a number of houses. Madhya Pradesh has been doing well. I think a thousand houses have been constructed, completed in Mysore. Like that a lot of activity of housing projects is going on all over the country. Recently we had a review meeting with the representatives of the State Governments. We are trying to see that more houses are consturcted for them. We have a scheme for building houses, which we call 'build your own house'. Here, of course, the response is not very much. So, far we have been able to construct only 3780 houses.

A point was very well been emphasised on bringing these workers into the cooperative societies. That is precisely the intention of the Government of India. In order

to encourage the cooperative movement among the Beedi workers, we are financing worksheds at 50% of cost for them. We have a very good response from Kerala. One hon. Member has referred to that Kerala experiment. They have been doing very well. So far, we have been able to construct 47 worksheds for the Beedi workers under the cooperative society. I think this is the areas where we really need to do more.

A question was raised about the unbranded bidi. Upto 20 lakhs of Beedi is exempted from excise duty. Why is should be so? I think it is a very valid point and I am personally inclined to agree with the hon. Members and to question why unbranded Beedis should be exmpted from the payment of excise duty. I assure the House that I will take up this matter with the Finance Ministry.

As far as the Provident Fund is concerned, again our figure is not very much impressive. Out of 44.72 lakhs so far we have been able to bring only 11.61 lakhs of them under the coverage of the Provident Fund. More needs to be done. As I said much more vigorous efforts has to be done in the northern and eastern part of India Even in this respect I think Western and Southern parts of India are doing very well.

Then where we are unable to establish the relationship between the employer and the employee, we have brought out an insurance scheme for them. Till date we have covered 10 lakh workers under the insurance scheme where workers are not to contribute anything, and the employer has also not to contribute anything. The contribution goes from the welfare fund and Social Security Fund of L.I.C. It is a very good scheme. We are trying to cover more and more areas. These are a few important points that have been raised by the hon. Members. I would like to thank them once again and assure them that it is our attempt to take up more and more welfare measures and to regulate their conditions of work. It is a continuous process.

The suggestions which have come from the hon. Members during this debate, will be examined and that they will be taken into consideration with all the seriousness and whenever it is necessary to bring in amendments to make some changes we will be willing to do so.

SHRIMATI MIRA DAS : You have not mentioned about the women workers.

SHRI P. A. SANGMA : The problem is that most of the Beedi workers belong to the Scheduled Castes and Tribes. And since Beedi are manufactured at home and male member of the family goes outside to work, the manufacturing part of the Beedi is done by the lady of the house and the children of the house. So, it is mainly the women and children who are engaged in Beedi making. Therefore, our whole attention at regulating the conditions of service and also Social Security measures cover workers and children.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : The question is :

> "That the Bill to amend the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 1. (Short Title and Commencement)

SHRI P. A. SANGMA : I move :

"That at page 1, line 4, for the figure '1990' the figure '1993' be *substituted*."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

ENACTING FORMULA

SHRI P. A. SANGMA : I move :

"That at page 1, line 1, *for* the word 'Forty-first' the word 'Forty-fourth be *substituted*."

The question was put and the motion was adopted. The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill. The Title was added to the Bill.

SHRI P. A. SANGMA : Sir, I move :

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1993

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : We shall now take up the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1993. Shri S. B. Chavanji.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) : I move :

"That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973, be taken into consideration."

There is an increasing realisation all over the world that acts of crime and terrorism are fast acquiring international complexion. This trend has been substantially facilitated by the rapid strides made in recent years in the field of transportation and communication. The nexus across countries between the perpetrators and supporters of crime and terrorism can be destroyed and the guilty brought to book only if the widest measure of cooperation is established between the actions of law-enforcing agencies of different countries. As a first step in this direction, an agreement between the Govt. of India and the Govt. of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was signed in London on 22nd September, 1992 to cooperate mutually in the investigation and prosecution of crime and the tracing, restraint and confiscation of the proceeds and instruments of crime and terrorist funds. The agreement between contracting States provides *inter alia* for search, attachment and forfeiture of property derived from the commission of an offence, assistance in search and transfer of persons wanted for criminal activity, assistance in investigation and furnishing of evidence, etc. In order to implement this agreement it has become necessary to amend the Criminal Procedure Code.

The Bill seeks to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 to provide for this.

I commend the Bill for consideration of this august House.

The question was proposed.

SHRI O. RAJAGOPAL (Madhya Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I will not say that the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1993 has come too early. Now after the recent agreement between the Government of India and the Government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland referred to by the hon. Minister, it has been found necessary to introduce this Bill. I support the objectives of this Bill. I do not know whether our agreement is confined to only Great Britain and Northern Ireland or it is applicable to all the countries. Even though the Statement of Objects and Reasons refers to only these countries, from the wording of the Bill it appears to me that it applies to all countries with whom we have no treaties on this subject. This treaty with other countries is absolutely essential.

Recently we had a very interesting case in the State of Kerala. A Keralite who was employed in a Gulf country had swindled away a few crores of rupees. Then, he came to India. The court in Kerala found him guilty. They have sentenced him to a few years in jail. They have asked him to pay Rs. 50,000 as fine. His photograph was published in all the newspapers. He was very happy. He was enjoying the whole thing. Though he had swindled away about Rs. 2 crores, he was fined only Rs. 50,000. He was enjoying the whole scene. It is a case where the whole property which he swindled should be forfeited and should be made available to the country which had lost it. This is an attempt by which such a provision is being made available in our statute also. Therefore, it is a welcome measure. I would like to see that such agreements are entered into with the various Gulf countries and other countries also. A number of people from India, specially from Kerala, are employed there and quite often, they commit